International Journal of Applied Research 2019; 5(1): 01-05

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(1): 01-05
www.allresearchjournal.com
Received: 01-11-2018
Accepted: 03-12-2018

Dr. Shunezi Yunus
Assistant Professor,
Arab Culture Department
Karamat Husain Muslim Girls P.G.College, Uttar Pradesh, India

Correspondence
Dr. Shunezi Yunus
Assistant Professor,
Arab Culture Department
Karamat Husain Muslim Girls P.G.College, Uttar Pradesh, India

आधुनिक युग में भारत मिस्र सम्बन्ध

Dr. Shunezi Yunus

यदि विस्तार पूर्वक दोनों देशों के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाए तो साफ़ दिखाई देगा कि यह दोनों महान देश सदा से निकटतम हैं। उसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद भी दोनों का सम्बन्ध निकटतम रहा तथा घनिष्ठता बढ़ती गई। और आज भी विदेशी सम्बन्धों में भारत के मिस्र से मधुर सम्बन्ध है। मिस्र एक अरब देश होने के अतिरिक्त आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक व शैक्षिक सम्बन्धों में भारत से बहुत निकट है। और दोनों की समस्याएं भी बहुत कुछ एक जैसी दिखाई पड़ती हैं, तथा दोनों ने एक दूसरे की समय–समय पर सहायता भी की। इस भाग में इन्हीं सम्बन्धों का विस्तारपूर्वक उल्लेख प्रस्तुत किया जा रहा है।

अंग्रेजों व फ्रांसीसियों से स्वतंत्रता के बाद मिस्र–भारत

26 जनवरी 1950 में भारत को गणतन्त्र राज्य की मान्यता प्राप्त हो गयी। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने का प्रयत्न किया उन्होने जनता को विशेष सुविधायें प्रदान की । स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया, जातिवाद की भावना में परिवर्तन, औद्योगिकरण, समाजवाद, योजनाओं तथा लोकतान्त्रिक प्रजातंत्र के द्वारा भारत के आधुनिकिकरण का प्रयास प्रारम्भ किया।

अब भारत में सामाजिक और सास्कृतिक प्रगति की दृष्टि से उद्योगो की आवश्यकता थी ।भारतीय कृषको की दशा सुधारने के लिये भारत सरकार ने उचित कदम उठायें बहुत से राज्यों में जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमिहीन कृषको को भूमि प्रदान की गयी तथा 2 अक्टूबर 1952 को पिछड़े वर्ग के विकास हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया।

अरब क्षेत्र में मिस्र की सदा ही अपनी एक अलग पहचान रही है। इसलिए 19 वीं शताब्दी में जब फ्रांस व ब्रिटेन ने इसे अपने अधिकार में लेना चाहा तो उन्होंने बहुत सतर्कता का परिचय दिया। उन्होंने मिस्र पर बाहुबल का जोर आज़माने के बजाए, पिठ्ठू शासकों के माध्यम से अपने हितों को पूरा किया। इसके अतिरिक्त फ्रांस व ब्रिटेन की इस रणनीति को मिस्र की जनता ने पसन्द नहीं किया। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन और फ्रांस के विरुद्ध मिस्र की जनता प्रतिरोध की साक्षी बनी। इस शताब्दी में वह विदेशी शक्तियों से अपने देश को स्वतंत्र तो नहीं करा पाई परन्तु उसने हार भी नहीं मानी।

1952 में जनता के विरोध ने एक नया रूप लिया तथा मिस्र की जनता ने जमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में अपने पिट्ठू बादशाह फारुक को गद्दी से उतार दिया और उनकी पूरी सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो गया। इस क्रांति ने जमाल अब्दुल नासिर को मिस्र का नायक तथा नेता बना दिया। नासिर जब तक सत्ता में रहे उन्होंने अपने देश को विदेशी प्रभाव से बचाये रखा। नासिर को फ्रांसीसी व अंग्रेजों का राजनीतिक हस्तक्षेप पसन्द नहीं था। इस संकट से उबरने के लिये वह यूरोप व अमेरिका से सहायता ले सकते थे परन्तु उनको यह भय था कि यदि वह ऐसा करेंगे तो पुनःदास न बन जायें। उन्हें देश काविकास तो पसन्द था परन्तु स्वतंत्रता के मूल्य पर नहीं। इसलिए उन्होंने भरसक प्रयास किये कि मिस्र की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए देश का विकास हो। उस समय यह संकट उन सभी देशों के साथ था जिन्होंने जल्दी ही उपनिवेशवाद से खुद को स्वतंत्र किया था। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन इसी का परिणाम था। तीसरी विश्व की जनता मिस्र की इस भूमिका को कभी नहीं भूल सकती। और वह उसके साथ निकटता बनाए हुए है।

अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही मिस्र की सत्ता पर सेना का अधिकार रहा। कर्नल नासिर भी सेना के अधिकारी थे, परन्तु यह अलग बात है कि उनके काल में मिस्र में तानाशाही नहीं स्थापित हो पायी। सेना की इसी भूमिका के कारण ही वहां तानाशाही शासन के विरुद्ध मिस्र की जनता सड़क पर उतरती रही। नासिर के अतिरिक्त स्वतंत्रता की लड़ाई में मोहम्मद नजीब का भी बराबर का योगदान था। उन्होंने सन् 1952 ई0 से 18 जून सन् 1953 ई0 तक मिस्र में क्रान्ति की,[1] तथा मिस्र की स्वतंत्रता के बाद 18 जून सन् 1953 ई0 में यह मिस्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। कुछ अपरिहार्य कारणों से 14 नवम्बर सन् 1954 ई0 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने कार्यकाल में मोहम्मद नजीब ने मिस्र की व्यवस्था देखने के अतिरिक्त भारत से सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। परन्तु शासन का अल्पकाल होने के कारण उनका यह प्रयास सफल न हो सका। इसी प्रकार मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर जिनका कार्यकाल 23 जून सन् 1956 ई0 से 28 जून सन् 1970 ई0 तक रहा तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से मैत्रीपूर्ण राजनैतिक सम्बन्ध थे।

मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू Non Align Movement (NAM) के अग्रणीय (जन्मदाता) थे।

भारत मिस्र के राजनैतिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का यह प्रमाण है कि सन् 1956 ई0 में श्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने देश को ब्रिटिश कॉमन वेल्थ से हटाने की धमकी देते हुए मिस्र का साथ दिया। 18 व 19 जुलाई सन् 1956 ई0 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, टीटू और जमाल अब्दुल नासिर ने कॉमन वेल्थ सम्मेलन में भाग लिया। इसी सन्दर्भ में इन लोगों ने 20 जुलाई को एक संयुक्त प्रपत्र निकाला, जो कि निम्नलिखित है–In the course of the visit to the Federal People's Republic of Yugoslavia of the President of the Republic of Egypt, Gamal Abdel Nasser, and of teh Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, talks between President Josip Broz Tito, President Nasser and Prime Minister Nehru took place at Brioni on 18 and 19 July 1956. During the talks which were conducted in an atmosphere of cordiality and friendship a detailed exchange of views took place on matters of common interest.

12 माह बाद इनकी पुनः बैठक हुई, जिसमें इन नेताओं ने एक–दूसरे के विचार बिन्दुओं पर सन्तुष्टि प्रकट की, क्योंकि इन सभी ने शान्ति के नियमों को अपने देशों में लागू किया। यह लोग संसार में लड़ाई–झगड़ों को समाप्त करना चाहते थे तथा उनकी सोच में एकरूपता विद्यमान थी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान के सम्बन्ध में उनके मत में एकरूपता होने के कारण वह एक–दूसरे से सहयोग देते रहे तथा जो नीति उनके देशों में लागू की गई, उसके सन्दर्भ में उन्होंने सन्तुष्टि प्रकट की, क्योंकि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी तथा दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों में मधुरता दिखाई दी। इन नेताओं ने इन सभी बातों को प्रोत्साहन दिया।

Bandung सम्मेलन में इन तीनों नेताओं ने यह अनुभव किया कि जब तक इस पृथ्वी पर तनाव की स्थिति बनी रहेगी तथा एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा, इससे विश्व की शान्ति भंग होती रहेगी। इन नेताओं ने विश्व के शक्तिशाली टुकड़ों में बँट जाने और एक–दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने पर चिंता व्यक्त की। उनका मानना था कि पूरे विश्व में शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिये अत्यधिक विनाशकारी हथियारों पर रोक लगाना व प्रयोगात्मक स्तर पर भी धमाकों को रोकना आवश्यक था, क्योंकि इससे मानवता को आघात पहुँचने के साथ–साथ देश के वातावरण का प्रदूषित होना भी निश्चित था। उन्होंने परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल उपयोगी हितों के लिये करने पर बल दिया।

भारत के प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि भारत युनाइटेड नेशन्स की नीति में पूर्णतः सहयोग देने के लिये तैयार है, परन्तु पूर्व के अनुभव एशिया के देशों की सहायता के रूप में कड़वे सिद्ध होंगे। अतः किसी सहायता के रूप में उनको छला गया तथा स्वार्थी लाभ उठाया गया। इस प्रकार इन एशियाई देशों में विदेशी सहायताओं के प्रति सचेतना उत्पन्न हो गयी। इसी सन्दर्भ को लेते हुए उद्घाटन भाषण में भारत ने पुनः स्पष्ट किया कि युनाइटेड नेशन्स की किसी भी नीति में यदि आर्थिक व राजनैतिक प्रभाव है या उसकी झलक दिखती है, तो भारत उससे सहमत नहीं होगा।[1] India and other countries in the East should be industrialized, should increase and modernize agricultural production, it is in the interests of those countries that can help in this process to help the Asian countries with capital equipment and their special experience. But in doing so, it is to be borne in mind that no Asian countries will welcome any such assiatance if there are conditions attached to it which lead to any kind of economic domination. We would rather delay our development, industrial or other, than submit to any kind of economic domination by any country.[2] इससे यह स्पष्ट है कि भारत भी अपनी प्रगति को बाधित करने के लिए तैयार था परन्तु दूसरे के दबाव में आकर नहीं।

24 अक्टूबर सन् 1956 ई0 में भारत सरकार द्वारा स्वेज कैनाल सम्बन्धी सुझाव दिये गये। यह सुझाव 26 जुलाई सन् 1956 ई0 में मिस्र के राष्ट्रपति नासिर द्वारा स्वेज कैनाल कम्पनी के सरकारी राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में था तथा जिसे अक्टूबर सन् 1956 ई0 में (न्ण्छण्) सुरक्षा परिषद द्वारा इसे समर्थन पारित किया गया।[1] भारत द्वारा मिस्र को दिये गये सुझाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है–The Government of India published on 24 October 1956 their proposals for the solution of the Suez Canal Issue. The following constitute the proposals:

I. Desirious that a peaceful and adequate solution of the situation which has arisen in respect of the suez Canal, in accord with the Charter, The principles and purposes of the United Nations and consistently with the sovereignty of Egypt, must be found and the way for negotiations opened on the basis of:

1) The recognition of the Suez Canal as an integral part of Egypt and as a waterway of international importance.
2) Free and uninterrupted navigation for all nations in accordance with the Convention of 1888;
3) The tolls and charges being just and equitable and the facilities of the Canal being available to all nations without discrimination;
4) The canal being maintained at all times in proper condition and in accordance with modern technical requirements relating to navigation; and
5) Co-operation between the Canal Authority and the users of the canal receiving due recognition.

सन् 1956 ई0 में ब्रिटेन तथा फ्रांस स्वेज कैनाल पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। इस अवसर पर भारत मिस्र का साथ देने से पीछे न हटा तथा भारत ने स्वेज नहर के सम्बन्ध में Internationalization Committee का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि मिस्र के पक्ष में था, परन्तु ब्रिटेन व फ्रांस के पक्ष में न होने के कारण इसे मान्यता न दी गई।[1] मिस्र की आन्तरिक समस्याओं में भी ब्रिटेन ने हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया था। स्वेज नहर का निर्माण व्यापारिक उद्देश्य से हुआ था, परन्तु मिस्र पर ब्रिटेन व फ्रांस का अधिकार बढ़ता चला गया।

ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका स्वेज नहर के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के पक्षधर थे परन्तु कर्नल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते हुए 26 जुलाई 1956 में सकन्दरिया में एक जोशीला भाषण दिया,[2] इस भाषण में नासिर ने मिस्र की जनता के सम्मुख कहा कि– ''स्वेज कैनाल कम्पनी मिस्र की कम्पनी बतायी गयी है जिसमें उसी देश के कानून के अन्तर्गत विचार है इस कम्पनी में ब्रिटेन के 44ः के शेयर, निर्देशकों की संख्या 32 है जिसमें से 9 ब्रिटेनी, 16 फ्रांसीसी, 5 मिस्री, 1 अमेरिकन तथा एक डच निर्देशक है। स्वेज कैनाल की छूट सन् 1968 ई0 में समाप्त हो जानी थी और मिस्री सरकार पूर्व व उस समय की दोनो ही ने साफ–साफ सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया था कि इन परामर्श का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। जो कि सन् 1856 ई0 की सन्धियों के अन्तर्गत थे। मिस्री सरकार का स्वेज कैनाल सम्बन्धी यह निर्णय तथा निवेशकों को बाजार मूल्य पर पैसा अदा करना यदि देनदारी हो तो मिस्री सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सभी देनदारियां जो कि अर्न्तराष्ट्रीय सन्धि

The internationalization of Suez Canal

सन् 1888 ई0 के अन्तर्गत थी तथा एग्लो इजिप्शिन एक्ट सन् 1954 ई0 के अन्तर्गत ही उन सभी देनदारियों को अदा करेगा।''[1] फिर स्वेज नहर विवाद का एक अन्य मुख्य कारण यह भी था कि सैनिक दृष्टि से नहर का महत्व होने के कारण पश्चिमी देशों की इसमें अधिक अभिरुचि थी तथा इसका व्यापारिक महत्व भी अत्यधिक था। यदि इस नहर को पश्चिमी देशों के लिये बन्द कर दिया जाता, तो एशिया के साथ व्यापार करने के लिये पश्चिमी देशों को हज़ारों मील का समुद्री मार्ग तय करना पड़ता। जिसके कारण अनेक कठिनाईयां उत्पन्न हो जाती, समय अधिक लगता और व्यापारिक व्यय भी बढ़ जाता।

भारत–मिस्र सम्बन्धों का राजनैतिक प्रभाव

मिस्र की स्वतंत्रता सम्बन्धी सोच भारत की विदेश नीति में दिखाई पड़ी। 1 जून सन् 1948 ई0 के United Nation's Economic Commission for Asia and the Far East Statecommand की बैठक में भारत द्वारा अपने उद्घाटन के भाषण में इस बात को स्वीकारा था, कि एशिया पीढ़ियों से एक स्थान पर स्थिर होने के साथ–साथ पिछड़ा हुआ था तथा विश्व की आर्थिक उन्नति में भी बहुत पीछे था। एशिया के सभी देशों को विकासशील होने के लिये औद्योगीकरण तकनीकी तथा अनुभव इत्यादि की दूसरे सामर्थ्य देशों से आवश्यकता थी। परन्तु एशिया का भारत जैसा देश यह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी उन्नति, विकास, औद्योगीकरण, नवीन कृषि उत्पाद में सहायक यंत्र इत्यादि दूसरे देश के आर्थिक दबाव में हों। यह एक ऐसा सच है जिसे प्रत्येक भारतवासी मानेगा।[1]

भारत मिस्र सम्बन्ध का यदि हम अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों देशों ने आज भी बहुत से समझौते किए हैं और यह समझौते सामाजिक, आर्थिक और सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में हुए हैं। इसका अनुमान इस रिपोर्ट से लग सकता है ।

A number of agreements covering various aspects of political, economic and cultural relations have been signed by the two countries. A Partnership Agreement between India and Egypt was initialed in Cairo in May 1999 during the first meeting of the India & Egypt Joint Business Group. It is an umbrella Agreement focusing on bilateral industrial cooperation for setting up of joint ventures with built–in exchange of expertise. The Agreement is yet to be signed. To give a further boost to bilateral economic relations a Preferential TRADE Agreement (PTA) and a new Double Tauation Avoidance Agreement (DTAA) are being negotiated by the two sides- Other important ongoing negotiations include Air Connectivity Talks and Merchant Shipping Agreement. The Tourism Cooperation Agreement has been ratified by both the countries.

जबकि इस प्रकार के समझौते नेहरू के काल में भी बहुत हुए हैं। इसका अनुमान मिस्र के नेता जमाल अब्दुल नासिर और पंडित नेहरू की भेटों से लगाया जा सकता है। चावन लाई द्वारा 7 पावर कान्फ्रेंस में मिस्र और भारत भी था।

स्वेज विवाद–

सन् 1956 ई0 में स्वेज कैनाल के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में नेहरू का रुख मध्यस्थ (Neutral) था। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने सरकारी उच्च अधिकारियों से स्वेज कैनाल के सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी न देने को कहा।

स्वेज कैनाल के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के सम्बन्ध में ब्रिटेन एक कान्फ्रेंस करवाना चाहता था। यह तत्व ज्ञात होने पर नेहरू ने नासिर को सलाह दी कि वह स्वयं इस बैठक की अगवानी करें। चूँकि इससे मिस्र का भविष्य जुड़ा है जो कि सह–सम्मति से ही हल हो सकता है।

पं0 नेहरू कर्नल नासिर को स्वेज कैनाल संबधी सुक्षाव देते हुए

पं0 नेहरू और कर्नल नासिर के सम्बन्धों का विवरण–

कई स्थानों पर पं0 नेहरू ने जमाल अब्दुल नासिर को महत्वपूर्ण सुझाव दिये। जिसमें से यह भी एक था कि लन्दन से लौटते समय जब जवाहर लाल नेहरू काहिरा आये, तो उन्होंने नासिर और उनके सहयोगियों से कहा कि वह मिस्र व इज़राइल विवाद को लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध कोई कड़े शब्दों का प्रयोग न करें और उससे सम्बन्धित उद्देश्यों को भी दृढ़ता से रखें। इस सुझाव के बाद नासिर की वाणी के विनम्र शब्दों के प्रयोग ने चर्चिल को भी प्रभावित किया।[1] पं0 जवाहर लाल नेहरू और कर्नल नासिर की मित्रता आधुनिक काल में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई।

भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा करने का जो कार्य पंडित जी ने किया, उससे कौन असहमत हो सकता है। मेरी दृष्टि में पंडित जी का दूसरा बड़ा कार्य भारत में लोकतंत्र को खड़ा करना था जिसकी जड़ें अब अत्यधिक परिपक्व हो चुकी हैं और जिसका लोहा सम्पूर्ण विश्व मानता है और भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है।

स्वस्थ लोकतंत्र

सन् 1952 में पंडित जी के नेतृत्व में देश के पहले आम चुनाव में स्वस्थ लोकतंत्र की जो नींव रखी गई थीं, वह वर्तमान समय में भी उपस्थित है (आपातकाल के 19 माह को छोड़कर)। प्रधानमंत्री

काल में विदेशी विभाग सदा नेहरू के पास रहा और इसी मध्य उन्होंने मार्शल टीटो, कर्नल नासिर तथा सुकाड़ों के साथ मिलकर गुट–निरपेक्ष आन्दोलन की नींव रखी, जो शीत युद्ध की समाप्ति से पहले तक काफी प्रभावी रहा।[1]

कर्नल नासिर ने सन् 1955 ई0 में कहा कि यदि हम दूसरों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ायेगें, तो दूसरे भी हमारे मित्र बने रहेगे जिससे देश की सीमाओं तथा हिमालय की सुरक्षा हो सकेगी। सन् 1955 ई0 में नासिर के विदेशी नीति से सम्बन्धित कदम ब कदम भारत के साथ होने पर चीन को आपत्ति हुई कि, ''नेहरू का भारत एक रोड़ा है''। भारत के सम्मान को अत्यधिक घात लग सकता है यदि वह चीन को इस मामले में सम्मिलित न करे।[2] परन्तु अंतिम समय में पंडित जी को कुछ असफलताओं का भी मुंह देखना पड़ा और चीन के साथ मित्रता करना अत्यंत भारी पड़ा।

यद्यपि चीन के साथ मित्रता का आरम्भ भी उन्होंने पूरी निष्ठा से किया था और पंचशील के सिद्धांत के साथ–साथ हिंदी चीनी भाई–भाई का नारा दिया, परन्तु 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने से पंडित जी भी बहुत दुःखी हुए और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उनकी मौत का कारण यह दुख भी था। 19वीं सदी के अन्तिम 25 वर्षों में तथा इसके बाद भी विदेशी व्यापार की बढ़ोत्तरी होती रही।[3] 12 जुलाई सन् 1962 ई0 में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनु भाई शाह ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में, आर्थिक विकास की समस्याओं के सन्दर्भ में काहिरा के सम्मेलन में भाग लिया।

20 अगस्त सन् 1963 ई0 के बाद 30 भारतीय टेक्नीशियन्स ने काहिरा के कारखाने में सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमानों को बनाने में मिस्र को सहयोग दिया। इन तकनीकी लोगों को मिस्र की सरकार ने भारत की सरकार की सहायता से चुना था।

सन् 1967 ई0 में अरब–इस्राईल की लड़ाई नें भी भारत ने मिस्र तथा अरबों का साथ दिया। मिस्र की राजनैतिक रणनीति की समय–समय पर भारत ने सराहना की। नेहरू ने कई देशों से आर्थिक व राजनैतिक सन्धियाँ कीं, परन्तु उन्होंने मिस्र को सबसे अधिक महत्व दिया। काहिरा भारत को अधिक मात्रा में रुई निर्यात करना चाहता था, परन्तु उस समय तक भारत स्वयं रुई के निर्यात में सक्षम हो गया। जिसके कारण मिस्र को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। आर्थिक कारणों का प्रभाव राजनैतिक स्थिति पर भी पड़ा। अतः दोनों देशों के सम्बन्ध इतने मधुर नहीं रहे, जितने कि पूर्व में थे। दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः परिपक्वता आने से पूर्व ही सन् 1970 ई0 में हृदयगति रुक जाने से कार्यालय में नासिर का देहान्त हो गया।

मिस्र के राजनैतिक नेता तथा उच्च अधिकारी अपने देश का दूसरे देशों से सम्बन्ध बनाने हेतु भिन्न–भिन्न देशों में जाया करते थे। इसी सन्दर्भ में अनवर सादात जो कि मिस्र के इस्लामिक कान्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल (सचिव) तथा 'अल गोम होरिया' नामक समाचार–पत्र के प्रशासक थे। (यह मिस्र का दैनिक समाचार–पत्र था) उन्होंने भारत का भ्रमण किया तथा पं0 जवाहरलाल नेहरू से भेंट की। उन्होंने बांग्लादेश, पाकिस्तान के अतिरिक्त सन् 1974 ई0 में भारत भ्रमण किया, ताकि वह यहाँ कि (सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक) परिस्थितियों से भली–भाँति अवगत हो सकें।[2] भारत ही नहीं अनवर सादात का एशिया तथा इण्डोनेशिया आदि सभी स्थानों से सम्पर्क बना रहता था। सन् 1977 ई0 में मिस्र के अनवर सादात ने येरुशलम का भ्रमण किया। इस राजनैतिक गतिशीलता को भारत ने वीरता का कदम बताया। मिस्र व इस्राईल के सहमति पत्र को मध्य–पूर्व की समस्याओं का निवारण का प्रथम कदम बताया। भारत आने पर सादात का नेहरू द्वारा स्वागत किया गया।

भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिये सन् 1979 ई0 में मिस्र ने भारत को तेल का निर्यात प्रारम्भ किया, जो कि भारत के कुल निर्यात का 0.5 प्रतिशत था तथा सन् 2000 ई0 में मिस्र से भारत को निर्यात किये जाने वाले तेल की मात्रा 95 प्रतिशत हो गई। तेल की आवश्यकता पूरी होने से भारत ने स्वयं को बहुत अच्छी स्थिति में पाया। भारतीय निवेशकारों में आत्मबल की भावना जाग्रत हुई तथा उन्हें मिस्र में अपना धन निवेश करने में पूर्णतः विश्वास था। इसी विश्वास के फलस्वरूप भारतीय पूँजीपतियों ने मिस्र में धन निवेश के प्रति रुचि दिखाई।

सर्वे में भी यह तथ्य सामने आये हैं कि भारतीय पूँजीपतियों की सोच मिस्र की अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक थी। वह बिना भय के अपनी पूँजी का निवेश मिस्र में करने को तैयार थे। सन् 2003 ई0 में (पेट्रोलियम) तेल के सम्बन्ध में भारत की रिलाइंस कम्पनी ने मिस्र को जनरल पेट्रोलियम कारपोरेशन से (ब्तनकम व्पस) कच्चा तेल सम्बन्धी हस्ताक्षर किया। सन् 2004 ई0 में मिस्र पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को गैस पाइप लाइन सम्बन्धी प्रस्ताव भी दिया।[1] दिल्ली रिपोर्ट सोमवार 10 दिसम्बर सन् 2007 ई0 में इण्डिया–इजिप्ट लिमिटेड मिस्र में नयी रिफाइनरी लगाने की संभावनाएँ ढूंढ रही है। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन मिस्र में अपनी तेल रिफाइनरी लगाने की संभावनाओं के लिये इजिप्ट–इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स को मिस्र भेज रही है। इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की चेयरमैन श्री मुकेश ने रिपोर्ट में बताया कि– मिस्री भागीदार है कि आपसी व्यापार में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुई। यूनाइटेड स्टेट, इटली तथा सउदी अरब के बाद भारत मिस्र का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया तथा भारत व मिस्र के व्यापारिक सम्बन्ध चौथे स्थान पर पहुँच गये।

दोनों नेताओं ने एक–दूसरे के रक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में सहमति व्यक्त की। मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाई कहते हुए भारत को हर संभव सहयोग देने को कहा तथा यह भी कहा कि वह भारत की सहायता के लिये हर समय तत्पर रहेगा। मुर्सी के शक्ति मे आने से पूर्व मिस्र कई वर्षो से कठिनाईयों से जकड़ा था मिस्र की भौगोलिक स्थिति एशिया व अफ्रिका के मध्य एक पुल की भाँति थी जो कि ग्लोबल ट्रेड रूट (Global Trade Route) बनाता है, जिसमें सक्षम लोग हैं वह भारत के लिये एक आकर्षण की जगह बनाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वह स्वयं मिस्र के राष्ट्रपति मुर्सी उत्पादक भागीदारी जैसे–सामाजिक तथा आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं हेतु तैयार है और मुर्सी ने मनमोहन सिंह से कहा – "We also agreed to enhance our defence exchanges and co-operation"

Egypt Genra Petrolium Corporation के साथ 9 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी और पेट्रोलियम केमिकल कॉम्प्लेक्स मिस्र में बनवायेगा।[1] यह सभी बातें इस बात का साक्ष्य हैं कि भारत के मिस्र के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध अति मधुर रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने सन् 2008 ई0 में भारत का भ्रमण किया तथा प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से भेंट की।

मिस्र की नवीन परिस्थितियों ने गति पकड़ी तथा वह अपने देश के विकास के लिये एक नयी ऊर्जा के साथ अग्रसर हुए। यही उचित समय था, जब भारत व मिस्र ने साथ मिलकर एक ऐसी योजना प्रारम्भ की जिसमें केवल विजय ही विजय (पद ॅपद ैपजनंजपवद) का स्थान था तथा पराजय की कोई संभावना नहीं थी। अतः भारत व मिस्र पारस्परिक आर्थिक विकास की नई ऊँचाईयाँ छूने लगे और सन् 2011–2012 ई0 में व्यापार ने पूर्व के वर्ष से 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की। हुस्नी मुबारक के सत्ता मुक्त होने के बाद मिस्र वही राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। अतः मोहम्मद मुर्सी के सत्ता में आने से पूर्व मिस्र में उथल–पुथल चल रही थी।

मोहम्मद मुर्सी के राष्ट्रपति बनने के पश्चात् भारत–मिस्र के व्यापार के नये आयाम खुल गये। मिस्र के स्टॉक बाज़ार में उछाल आना इस बात का संकेत था कि मोहम्मद मुर्सी ने मिस्र की आर्थिक स्थिति के मार्ग प्रशस्त किये। यही नहीं, मिस्र के

राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने 4 दिन का (मार्च 2013 में) भारत भ्रमण किया। जिसमें बहुत से समझौते हस्ताक्षर किये। ताकि परस्पर व्यापार को गतिशीलता प्राप्त हो। तकनीकी साइबर सुरक्षा, लघु तथा कुटीर उद्योग, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा भारत व मिस्र के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये हर सम्भव प्रयास किये गये। समय इस बात का साक्ष्य.

References

1. The Indian Express. 1971, 21.
2. Appadorai A. Select document on India Forgein Policy and relation. Oxford, New Delhi: Oxford University Press, 1947-1972, IInd.
3. Bindra APS. Suez Thombosis Causes and Prospects. Vikas Publications, 1969.
4. Nehru Jawaharlal. The Discovery of India. Culcutta: The Signet Press Fifth Painting, 1918.
5. Narayan Col BK. Anwar El Sadat man with mission. New Delhi: Vikas Publication House Pvt.Ltd. Delhi press Jhandowalamm, 1977.
6. Sarvepalli Gopal. Jawaharlal Nehru A Biography. Delhi, Bombey, Culcutta: Oxford University, 1947-1956, 4.
7. Times of India. 1963, 20.
8. The Indian Express. 1971, 21.
9. Narayan Col BK. Anwar El Sadat man with mission. New Delhi: Vikas Publication House Pvt. Ltd. Delhi press Jhandowalamm, 1977.
10. The Hindu. Manmohan Time, 2008, 19.
11. Gulf News. 2009, 19.
12. Oil and Gas Journal. Penwell Publishing
13. सुरेश चन्द्र, आधुनिक विश्व का इतिहास, प्रथम संस्करण, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली,